"We cannot rule out the use of nuclear weapons on a regional basis"—note the words 'regional basis'—when national interests are involved".

Now, in view of the present American posture being one of putting out threats of use of nuclear weapons and of seeking support for direct military intervention in Angola and other areas, I should like to know whether the Government, apart from establishing our Embassy there, would take other steps in consultation with the other like-minded nations in order to see that the liberation movement in Southern Africa advances and that the security of that region is not disturbed at all and that a proper reply is given to these methods of nuclear blackmail and other threats put out by Dr. Kissinger.

SHRI Y. B. CHAVAN : Sir, as we all know, this policy of intervention in Angola has been defeated and the whole world will know exactly that all these big words that were used by....

SHRI BHUPESH GUPTA : What ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I said, all these big words that were used by the big powers..

SHRI BHUPESH GUPTA : Only big words ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I will say, 'threatening words'. These threatening words, I would say, ultimately proved to be empty words. But there is no doubt about this that we are certainly against it, against any use of nuclear weapons either regionally or in any way and, certainly, we have expressed our views on this matter.

As regards the question of the attitude to be adopted about the liberation struggle in Southern Africa, as the honourable Members knows, this question was discussed in the Commonwealth Heads of States' Conference that was held in Kingston in which our Prime Minister represented our country and this question has been constantly before the Non-aligned Nation's Conference and the Co-ordination Bureau would be meeting some time towards the end of May or early June and I am sure that the entire question will be examined in all its aspects.

MR. CHAIRMAN : All right. Next question.

*126. [*The Questioner (Shri S. Kumaran) was absent. For answer,* vide *cols* 32—33. infra].

*127. [*The Questioners (Shri Sasankasekhar Sanyal and Shri Salil Kumar Ganguli) were absent. For answer* vide *cols.* 33. infra.]

*128. [*Transferred to the 23rd March,* 1976].

129. [*The Questioners (Shri Balram Das and Shri Chakrapani Shukla) were absent. For answer,* vide *cols.* 33—34 infra].

Free Movement of Tourist Vehicles

*130. SHRI KHURSHEED ALAM KHAN :
SHRI IBRAHIM KALANIYA :
SHRI JAGDISH JOSHI :
SHRI KASIM ALI ABID :

Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) Whether the is a fact that hhe State Governments have agreed to allow free movement of tourist vehicles within their respective jurisdiction ;

(b) whether any uniform specification and dimensions for such vehicles have been laid down; and

(c) whether any model rules have been framed for the State Governments to insuring uniformity of quality transport ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI DALBIR SINGH) : (a) Presumably, the reference is to unhindered movement of tourist vehicles of one State in the others. If so, the position is that most of the States/Union Territories have agreed to the arrangement.

(b) Yes, Sir.

(c) Guidelines have been forwarded to the State Governments for the consideration of the Transport Authorities in granting permits for tourist vehicles under Section 63(7) of the Motor Vehicles Act, 1939, to ensure that only tourist vehicle operators of standing and experience get such permits.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Jagdish Joshi.

श्री जगदीश जोशी : क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यों को टूरिस्ट व्हीकिल्स पर्मिट देने का औसतन कोटा किस आधार पर केन्द्र के द्वारा निर्धारित किया गया है और गाइडलाइंस के क्या-क्या मुख्य मुद्दे हैं ?

श्री दलबीर सिंह : कुछ ऐसा देखा गया कि सारे स्टेटस को बराबर बराबर पर्मिट्स दे दिए जायें। तो इस आधार को सामने रखते हुए नोटिफिकेशन इश्यू किया गया है सेक्शन 63(7) के नीचे जिसमें यह तय किया गया है कि 100 पर्मिट्स टैक्सी के दिए जाएं और 25 टुअरिस्ट कोचों के लिए दिए जाएं। वह हर स्टेट को इस आधार पर दे दिया गया है। जहां तक गाइडलाइंस के इश्यू करने का सवाल है उसके अन्दर यह दिया गया है कि सारे जो पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज वगैरह हैं उन को भी प्रेफरेंस दिया जाए और जैसा कि मेन आन्सर के अन्दर कहा गया है कि जो टुअरिज्म के क्षेत्र में अच्छा एक्सपीरियेंस रखने वाले हैं उनको दिया जाए, और एयर कंडीशण्ड कोचेज वगैरह को अच्छी तरह से, ठीक ढंग से, देखा जाए; उनके स्पेसिफिकेशंस वगैरह भी ठीक हों। तो इस तरह के गाइडलाइंस की एक चिट्ठी स्टेट गवर्नमेन्टस को लिखी गई है जिसके आधार पर इस स्कीम के ऊपर कार्यवाही होगी।

श्री जगदीश जोशी : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने संख्या निर्धारित की है, 100 टैक्सी की और 25 कोचों की प्रत्येक राज्य के लिए, तो किसी राज्य की एरिया, क्षेत्रफल, काफी बड़ा है, ज्यादा स्थान है और किसी राज्य में स्थान भी कम है और क्षेत्रफल भी छोटा है, तो स्थान और क्षेत्रफल इन दोनों को क्या इस प्रकार का निर्धारण करते समय ध्यान में नहीं रखा गया, क्योंकि एक जगह काफी साधन रहेंगे, उन साधनों का पूरा इस्तेमाल नहीं हो सकेगा और एक जगह साधन भी कम रहेंगे और लोग नहीं पहुंच सकेंगे। मैं उदाहरण के लिए निवेदन कर दूं, जैसे मध्य प्रदेश है जहां ज्यादा रेलवे नहीं है और एक कोने से दूसरे कोने में कम से कम 500-700 मील का फर्क पड़ता है और 25 कोचेज में मध्य प्रदेश का एक हिस्सा पूरा नहीं होता है। इस प्रकार जो बड़े राज्य हैं, उन की आवश्यकताओं को देख कर क्या उनके वास्ते ज्यादा कोचेज होने पर विचार करने का कोई इरादा सरकार का है ?

डा० जी० एस० ढिल्लों : माननीय सभापति जी, यह जो आनरेबल मेम्बर ने कहा है कि मैं समझता हूं उन्होंने ठीक कहा है। हमने शुरू में तो ऐसा कर दिया है। मेरे ध्यान में ये बातें बाद में लाई गई। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसको उठाया है। हम इसके ऊपर दोबारा विचार करेंगे और देखेंगे कि जहां कहीं जरूरत ज्यादा है या प्रांत का साइज ज्यादा बड़ा है तो ऐसी चीजें जरूर ध्यान में रखेंगे।

श्री ओम् प्रकाश त्यागी : सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा, अभी जो मन्त्री महोदय, ने यह बात बतायी है कि पर्यटक गाड़ियों के सम्बन्ध में उन्होंने गाइडलाइंन दिया है, तो क्या इन गाड़ियों का पर्मिट विशेष रूप से बेकार पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स को दिया जाएगा ताकि उनको जाब भी मिल जाए और बेरोजगार न रहें ? यदि पढ़े-लिखे नौजवानों को यह काम सौंपा जाए तो पर्यटकों के लिए भी सहायक होगा और हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवानों की रोजी लग जाएगी।

श्री दलबीर सिंह : त्यागी जी की हमदर्दी ग्रेज्युएटो से अच्छी नजर आती है, लेकिन जहां तक टूरिस्टों का सम्बन्ध है, उसके अन्दर तो हमें एक स्टैन्डर्ड चाहिए क्योंकि टूरिस्ट का जो काम है, वह सारी दुनिया में चलता है। हमारे देश में टूरिस्टों के सम्बन्ध में जो कार्य

चल रहा है, अगर हम उसमें स्टेन्डर्ड के हिसाब से पीछे रह जाएं तो ठीक नहीं होगा। इसलिए जिनको इस बारे में तजर्बा है, जो इस कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं, उन्हीं को यह कार्य दिया जाता है. और इसी के आधार पर स्टेटों को गाइड लाइन्स इश्यू किए गए हैं। ग्रेज्युएटों के लिए तो और भी कई स्कीमें बनाई गई हैं और उन्हें तरह तरह के इंसैन्टिव्ह दिये जा रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : आपने दिल्ली में ग्रेज्युएटों के लिए मिनी बस का कोटा दिया है। जब दिल्ली में मिनी बसों के सम्बन्ध में कोटा दिया जा सकता है तो इस सम्बन्ध में क्यों नहीं दिया जा सकता है ?

श्री दलबीर सिंह : बसों में और इसमें कुछ फर्क है। बसों का जो काम है वह ऐसा है कि उसके अन्दर ज्यादा लोगों को काम दिया जा सकता है। यह जो कोचेज और टैक्सी का काम है, वह एक स्पेशल नेचर का काम है और जिन्हें इसमें तजुर्बा होता है उन्हें ही यह काम दिया जा सकता है। इस काम में बिहेवियर और दूसरे स्टैन्डर्ड का भी ख्याल रखना पड़ता है जिसके द्वारा देश में टूरिज्म के सम्बन्ध में एक स्टेन्डर्ड कायम हो सके। इन सब बातों को खयाल में रखकर हमने इस आधार पर स्टेटों को गाइड लाइनें दी हैं।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : इसमें बहुत घोटाला हो रहा है।

SHRI B. V. ABDULLA KOYA : Sir, when the tourist taxis want to ply outside their own State, they find it very difficult to get permits and they are so often harassed by the State police of other States. Is there any uniform policy for allowing these tourist taxis of a particular State to go to the neighbouring States without much harassment ?

SHRI DALBIR SINGH : It is being provided in the instructions which are being issued that the permits should be issued at one place.

SHRI JAGAN NATH BHARDWAJ : In the interest of the co-operative working in the country, will the Minister consider the desirability of reserving a certain percentage for the co-operatives ?

SHRI DALBIR SINGH : Sir, the guidelines which have been issued do not provide for any special reservation.

MR. CHAIRMAN : You can consider that.

SHRI DALBIR SINGH : The suggestion has been noted by us.

*131. [*The questioners (Shri Salil Kumar Ganguli and Shri Sasankasekhar Sanyal) were absent. For answer,* vide *cols* 34 infra]

Rise in Postal Tariffs

*132. SHRIMATI SUMITRA G. KULKARNI :†
DR. Z. A. AHMAD :
SHRI JAGDISH JOSHI :
PROF. N. M. KAMBLE :
DR. K. MATHEW KURIAN :

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have with effect from the 1st March 1976 increased postal tariffs;

(b) if so, the details there of and the reasons therefor;

(c) whether it is a fact that the increased rates of money order tariff and public telephone call charges are likely to hit the lower and middle classes of the people; and

(d) if so, whether Government purpose to reconsider their decision in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI JAGANNATH PAHADIA) : (a) Yes, Sir. Tariffs for certain Postal services have been enhanced.

(b) Details of revised postal tariffs are indicated in the statement placed on the Table of the House.

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Sumitra G. Kulkarni